

नाबार्ड ने झारखंड के लिये बनाई 43 हजार करोड़ की क्रेडिट योजना

चर्चा में क्यों?

29 मार्च, 2023 को राँची में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने झारखंड मंत्रालय सभागार में स्टेट क्रेडिट सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें नाबार्ड ने वर्ष 2023-24 में झारखंड के लिये 43,725 करोड़ रुपए की राज्य क्रेडिट योजना प्रस्तुत की।

प्रमुख बिंदु

- यह क्रेडिट योजना वित्तीय वर्ष 2022-23 के 34,458 करोड़ रुपए से करीब 9,267 करोड़ रुपए ज्यादा है।
- कार्यक्रम का थीम 'राज्य बजट का क्रेडिट प्लान के साथ प्रसार' रखा गया था।
- इस अवसर पर नाबार्ड के सीजीएम एमएस राव ने स्टेट क्रेडिट सेमिनार के महत्त्व और उद्देश्य पर प्रकाश डाला तथा किसानों के लाभ के लिये राज्य में अधिक किसान उत्पादक संगठनों के गठन तथा उनके द्वारा हाई-टेक कृषि अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने नाबार्ड की ओर से स्टेट फोकस पेपर प्रस्तुत किया।
- स्टेट फोकस पेपर में स्पष्ट किया गया है कि प्रदेश के सभी 24 जिलों में राज्य के 4000 करोड़ रुपए के कृषि ऋण के मुकाबले बैंकों द्वारा 15,000 करोड़ ऋण दिया सकता है। राज्य के किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिये कई योजनाओं में वित्तीय मदद में इजाफा किया गया है। इस क्षेत्र को प्राथमिकता देने से बेरोजगारी, गरीबी और पलायन की स्थिति पर नियंत्रण किया जा सकेगा।
- इस बार केंद्र सरकार की तरह ही नाबार्ड का फोकस सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग पर दिखा। इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा 51% ऋण संभावना देखते हुए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग में 22071.87 करोड़ रुपए का ऋण प्रस्ताव रखा गया है।

